जीआईएस : 13 हजार करोड़ के करार धरातल पर उतरने को तैयार

सीएम योगी बोले- इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन यूनिट का गठन होगा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में मिले निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन और सतत मॉनीटरिंग के लिए सभी विभागों में इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 हजार करोड़ रुपये के हुए करार तुरंत धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। 3.90 लाख करोड़ के करार पर दो साल में उत्पादन शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिव स्तर के अधिकारी यूनिट के मुखिया होंगे। उन्होंने अधिकारियों को करार धरातल पर उतारने का रोडमैप सौंपा। कहा कि हर करार के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यूनिट अपने विभाग से जुड़े हर निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन और निवेशकों से संवाद-संपर्क के लिए जिम्मेदार होगी।

विशेष सचिव और इससे ऊपर के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्टरवार अथवा निवेश प्रस्ताव वार मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। कार्य की प्रगति संबंधित अधिकारी की दक्षता का प्रमाण बनेगी। हर एक प्रस्ताव की टाइमलाइन तय की जाएगी।

हर करार के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे

अगस्त तक पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी

मुख्यमंत्री ने इन करारों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों को भी सौंपी है। मंगलवार सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने जल्द से जल्द यूनिट स्थापना की कार्यवाही शुरू कराने का एजेंडा मंत्रियों को सौंपा। कहा कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में जाकर वहां हुए करार पर कार्यवाही के लिए उद्योग बंधु और व्यापार बंधु के साथ बैठक करें।

- सीएम ने कहा कि सरकार आगामी छह महीने (अगस्त तक) में बड़ी संख्या में निवेश प्रस्तावों की जमीन पर उतारते हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करेगी।

निवेशकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी फाइल लंबित न रहे। निर्णय में कतई देरी न हो।

यह है कार्ययोजना

- 2.80 लाख करोड़ के 29 करार पब्लिक सेक्टर यूनिटों की ओर से मिले हैं। इन प्रोजेक्ट पर तत्काल काम शुरू किया जाएगा।
- पीपीपी मोड के 2.45 लाख करोड़ के 99 करार पर जल्द क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है।
- 3.90 लाख करोड़ के प्रस्ताव दो साल में धरातल पर उतर सकते हैं।
- 4.11 लाख करोड़ के 782 प्रस्तावों पर निवेशकर्ता की आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा।
- विदेशी निवेशकों की सुविधा को देखते हुए औद्योगिक विकास विभाग की ओर से कॉल सेंटर की स्थापना होगी।
- प्रदेश में पर्याप्त लैंडबैंक उपलब्ध है फिर भी निवेशकर्ता की रुचि, प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार भूमि उपलब्ध कराएंगे। इसमें राजस्व विभाग और सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बड़ी भूमिका होगी।
- सिंक यूनिट की भूमि का उपयोग करने के लिए योजना बनाएंगे। केंद्र सरकार से सहयोग भी लेंगे।
- राज्य स्तर पर उद्योग बंधु की बैठक महीने में तीन बार होगी। जिला स्तर पर हर महीने बैठक होगी।
- 10 उद्यमी मित्र राष्ट्रीय स्तर पर तैनात किए जाएंगे। अथॉरिटी लेवल पर न्यूनतम 25 और हर जिले में न्यूनतम एक उद्यमी मित्र की तैनाती की जाएगी।